सामान्य अध्ययन (टेस्ट - II)

GENERAL STUDIES (Test - II)

मॉड्यूल - II / Module - II

DTVF/17–M–GS2

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): विक्रम गंगवार

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? | हाँ | ✓ | नहीं | |

मोबाइल न. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 30/07/2017

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2017] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2017]: 0 4 2 3 1 3 2

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिंदी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): (B)

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न हैं।

Evaluation Analysis

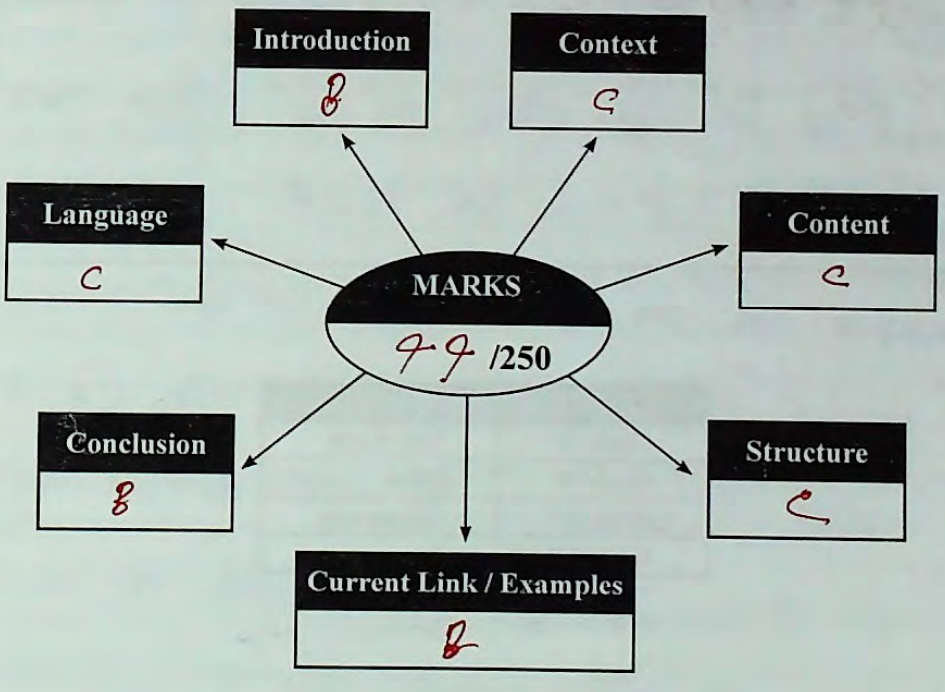

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

व्यापक विश्लेषण / Macro Analysis

- प्रश्न की मांग के ध्यान में रखकर समग्रता से विषयवस्तु को प्रस्तुत कीजिए।
- गलत सूचनाओं के प्रस्तुतीकरण से बचने का प्रयास कीजिए।
- विचारधारात्मक स्पष्टता का ध्यान रखिए।
- शब्द-सीमा का ध्यान रखिए।
- विभिन्न स्तरों पर कमियों को दूर कीजिए।

Grade Card	
Grade 'A'	Very Good
Grade 'B'	Good
✓ Grade 'C'	Satisfactory
Grade 'D'	Poor

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

1. "भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब सत्य को खोजने की बजाय व्यावसायिक हितों से निर्देश प्राप्त कर रहा है।" उपर्युक्त कथन का 'पेड-न्यूज़' की पृष्ठभूमि में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये तथा जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के संबंध में अपने सुझाव भी दीजिये। (250 शब्द) 12.5

"The fourth pillar of Indian democracy is now being guided by commercial considerations rather than pursuit of truth". Critically examine the above statement in the background of paid news and also add your suggestions in reference with the Representation of the People's Act, 1951. (250 words) 12.5

भारतीय लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के अतिरिक्त चौथे स्तम्भ के रूप में मीडिया की चर्चा की जाती है। मीडिया की भूमिका लोकतंत्र के विकास एवं गतिशील करने में अति महत्वपूर्ण होती है।

परंतु वर्तमान में मीडिया की नकारात्मक प्रवृत्तियों या व्यवसायिक हितों से संचालित होने के कारण इसका भारतीय लोकतंत्र पर विपरीत प्रभाव पड रहा है।

'पेड-न्यूज' ऐसी न्यूज होती है जो लगातार चैनल पर चलायी जाती है तथा सत्य या असत्य के प्रति जनता की मनोवृत्ति को बदलती है पेड-न्यूज पैसा देकर भी चैनल पर चलवाई जाती हैं जिससे जनता को वास्तविक जानकारी नहीं मिल पाती है और किसी सूचना के प्रति एकतरफा दृष्टिकोण या गलत

अच्छा प्रयास किया है।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

धारणा उत्पन्न हो जाती है।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के द्वारा पेड-न्यूज पर प्रभावयुक्त प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए इस संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं -

— यदि कोई सरकार का व्यक्ति इसमें संलिप्त हो तो तुरंत उसे पद से हटाया जाये या अयोग्य करार दिया जाये जैसे हाल ही में म०प्र० में एक राजनेता पर कार्यवाही की गई।

— मीडिया चैनलों पर नकेल कसने हेतु प्रावधान किये जाये तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत किया जाये।

— यदि किसी पार्टी विशेष का चैनल ऐसी न्यूज प्रसारित करे तो निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित हो।

इस प्रकार उपरोक्त उपायों का प्रयोग

पेड - न्यूज

आलोचनात्मक परीक्षण के अंतर्गत सभी आयामों पर चर्चा कीजिए

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

करके पेड न्यूज की गतिविधियों पर अंकुश लगाकर मीडिया का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है।

आगे की राह (Way forward)

उचित निष्कर्ष भी लिखिए

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	D	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

2. यद्यपि भारत 'ब्राजील घोषणापत्र' का हस्ताक्षरकर्त्ता देश है, फिर भी यहाँ सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Though India is a signatory to 'Brasilia Declaration', the road accidents can be termed as national crisis, illustrate. Examine the Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2016. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संक्षिप्त लेकिन पर्याप्त विवरण दीजिए

'ब्राजील घोषणा पत्र' के अन्तर्गत विभिन्न देशों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर कम करने की बात कही गयी थी। भारत भी इस घोषणापत्र का हस्ताक्षरकर्ता देश है परन्तु सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर काफी प्रयास करने के बावजूद भारत में सड़क दुर्घटनाएँ कम नहीं हो रही हैं।

सड़क दुर्घटनाओं को राष्ट्रीय संकट कहा जा सकता है क्योंकि -

उचित तर्क, आंकड़ें दें

- इससे मानव संसाधन की क्षति होती है।
- स्वास्थ्य सेवाओं पर अनावश्यक खर्च बढ़ता है।
- बच्चों, महिला, विकलांगों पर विपरीत प्रभाव
- आवास‍श्यक संरचना के अभाव का सूचक
- तकनीक रुग्णता का प्रतीक

द्वारा सड़क दुर्घटना को राष्ट्रीय संकट कहे जाने के उदाहरण दीजिए

भारत में साल-दर-साल दुर्घटनाओं

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

की संख्या आशातीत वृद्धि हो रही है।

इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक लाया जा रहा है यद्यपि अभी इसको लेकर संसद में गतिरोध है।

इस विधेयक में दुर्घटनाओं को कम करने, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने, चालकों के लिए दिशा निर्देश आदि प्रावधान किये गये हैं।

परन्तु इस विधेयक के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इसके संसद से पास होने तथा पास होने के बाद उचित क्रियान्वयन को लेकर है। अतः प्रयास किया जाना चाहिए इस विधेयक को उचित रूप से क्रियान्वित कर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाकर राष्ट्रीय क्षति को कम किया जाये।

विधेयक के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए इससे जुड़े न्यायोचित उल्लेख कीजिए

निष्कर्ष में सामान्य बात न करके उचित आगे की राह way forward प्रस्तुत कीजिए

2

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

3. हाल ही में भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों की पूर्व-सेंसरशिप के लिये चर्चा में रहा। क्या इस तरह की सेंसरशिप स्वामित्व (कॉपीराइट) और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? इसके विवादित पक्षों पर प्रकाश डालिये तथा भारतीय सिनेमा की समग्रता तथा भारत की विशिष्ट संस्कृति के संबंध में अपने सुझाव दीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recently censor board of India was in news for pre censorship of films. Is pre censorship violates copyrights and fundamental rights. Highlight the areas of controversy and put your suggestions for integrity of Indian cinema and ethnicity of Indian culture. (250 words) 12.5

भारतीय सेंसर बोर्ड का गठन फिल्मों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने तथा अनावश्यक या विभ्रात-कारी दृश्यों की काट-छांट करने के लिए किया गया था। अभी हाल ही में उड़ता पंजाब, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, इंदु सरकार आदि फिल्मों को लेकर भारतीय सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई तथा उन पर कई दृश्यों की काट छांट भी की।

इन्ही संदर्भ में सत्यजीत रे कमेटी का गठन भी किया गया ताकि सेंसरशिप के कार्य का मूल्यांकन किया जा सके इस कमेटी ने स्पष्ट सुझाव दिया कि भारतीय सेंसर बोर्ड को दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए कि वह उस फिल्म के प्रति क्या नजरिया रखते हैं।

हालिया घटनाओं या अधि उल्लेख कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड फ़िल्म द्वारा किये जा रहे कार्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन भी करते हैं तथा संविधान का उल्लंघन भी क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है जिस पर सेक्युलर युक्तियुक्त ढंग के अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

इसलिए सेंसर बोर्ड एवं भारतीय संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं—

- सेंसर बोर्ड द्वारा राष्ट्रद्रोही, सांप्रदायिक तत्वों को छोड़कर अन्य पर प्रतिबंध लगाते से बचना चाहिए।
- भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधुनिक भारतीय समाज की स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए।
- अश्लीलता से बचना चाहिए
- सेंसर बोर्ड में पदाधिकारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता व भारतीय समाज के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।

उपरोक्त उपायों को अपनाकर निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

उड़ता पंजाब के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख कीजिए

3

आगे की राह (The way forward)

उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश का भी उल्लेख कीजिए

इसे तोर पर भी अपनाएं

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

4. "संविधान संसद को शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है तथा संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।" इस कथन को पृष्ठभूमि में रखते हुए क्या आप सोचते हैं कि संसद के कामकाज के नियंत्रण तथा इसे सुगम बनाने के लिये एक निगरानी आयोग की आवश्यकता समय की मांग है? (250 शब्द) 12.5

"The Constitution provides powers and immunities to the Parliament and the Parliament can amend the Constitution". In the background of above statement, do you think a monitoring commission is the need of the hour to control and facilitate the functioning of the Parliament? (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारतीय शासन प्रणाली में संविधान सर्वोच्च है तथा संविधान ने विधि या कानून निर्माण की शक्ति संसद को प्रदान की है ताकि जनता के हितों को ध्यान में रखकर विधियों का निर्माण किया जा सके। इसके लिए संसद को उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई हैं जिन्हें संसदीय विशेषाधिकार के नाम से जाना जाता है।

संसदीय उन्मुक्तियों के अंतर्गत संसद की कार्यवाही के प्रसारण का प्रतिबंध, संसद में व्यक्त किये गये विचार, मतदान का न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर होना आदि। यह उन्मुक्तियां इसलिए हैं ताकि संसद स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सके।

दूसरी तरफ संसद संविधान में संशोधन

प्राप्त उन्मुक्तियों व शक्तियों के लाभों के साथ चुनौतियों का भी उल्लेख कीजिए/

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

कर सकती है परन्तु केशवानंद भारती (1973) के मामले मे स्पष्ट किया गया कि आधारभूत ढांचे को छोड़कर जो संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।

इसी परिप्रेक्ष्य में यदि संसद के कार्यों के निर्वहन के लिए एक निगरानी आयोग की बात की जा रही है। इसका आयोग के लाभ हो सकते है —

- संसदीय कार्यों के उचित कार्यान्वयन मे
- संसद द्वारा समय बर्बादी को रोकने में
- संसद के सदस्यों के आचरण पर निगरानी
- नियमित बैठकों, सत्रों के चलने हेतु

परंतु इसके कुछ नुकसान भी हैं —

- संसद सदस्य की स्वतंत्रता पर अंकुश
- विशेषाधिकारों पर अंकुश
- संसद में एक और बाधा उत्पन्न होना

इस प्रकार उपरोक्त सभी तथ्यों का मूल्यांकन करने के बाद ही निगरानी आयोग का गठन होना चाहिए ताकि संसदीय गरिमा बनी रहे तथा

आयोग की आवश्यकता का विश्लेषण मौजूदा प्रावधानों के संसदीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रयोग किये जाने का उल्लेख कीजिए। यथा बजट, महाभियोग, प्रश्नकाल व कटौती, शून्य काल आदि की कल्पना स्पष्ट।

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली–9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

जनता के लिए उचित कानूनों का निर्माण भी होता रहे।

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	–	0.5	0.5	–	–	0.5	
Grade	–			–	–		✓

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

5. कुछ राज्यों और क्षेत्रों को प्राप्त विशेष दर्जा अधिक जनांदोलनों को भड़काने का काम करता है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

The special status to some states and certain regions provoke more mass agitation. Critically examine. (250 words) 12.5

भारत में भौगोलिक पिछड़ेपन, आर्थिक विषमताओं, परिवहन-संचार संबंधी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ राज्यों एवं क्षेत्रों को विशेष राज्य एवं क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है।

विशेष राज्य एवं क्षेत्रों के लाभ -

- अधिक अनुदान की प्राप्ति (90% अनुदान, 10% ऋण)
- इनके लिए विशेष योजनाएं
- परिवहन-संचार साधनों का विकास
- शिक्षा के क्षेत्र में नये प्रयास

परन्तु इसी संदर्भ में भारत में उत्तरी पर्वतीय राज्यों एवं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। परन्तु इनको देखते हुए अब बहुत से राज्य विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं उदाहरण के लिए बिहार, तेलंगाना आदि।

उद्देश्य, विकास, परिवहन, संचार, निर्धारित पैमानों का उल्लेख कीजिए

स्प. अंश के संवैधानिक एवं अवैधानिक का उल्लेख कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

इसके लिए इन राज्यों एवं क्षेत्रों में जनांदोलन भी उभर रहे हैं ताकि इनकी मांग को राष्ट्रीय स्तर पर सुना जा सके जिसके कारण इन राज्यों में विकास योजनाओं का कार्य रुक जाता है तथा राज्य सरकारें केंद्र पर अनावश्यक दबाव डालती हैं जिससे संघवाद को भी चोट पहुंचती है।

इस दृष्टि से उचित उपाय यह हो सकता है कि इन राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाये या नहीं इसको लेकर उचित मापदंडों पर उन्हें देखना चाहिए साथ ही सुशासन, पंचायती राज एवं विकेन्द्रीकरण के द्वारा राज्यों एवं क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में विशेष योजनाएं चलायी जा सकती हैं जैसे - पर्वत विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम।

इस तरह इन उपायों को अपनाकर न केवल इन समस्याओं का समाधान होगा अपितु संघवाद को भी मूर्त रूप मिलेगा।

3

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

6. (a) आम लोगों को त्वरित न्यायिक सेवाएँ प्रदान करने के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन समय की आवश्यकता है? 6

The creation of All India Judicial Services (AIJS) is the need of the hour for providing fast judicial services to the common people. 6

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

वर्तमान में बढ़ते मुकदमों के बोझ, धीमी गति से मिलता न्याय तथा न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होना चाहिए जिसकी मांग स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन निम्नलिखित कारणों से जरूरी है-

- त्वरित न्याय मिल सकेगा
- योग्यताओं का चयन होगा
- मुकदमों का बोझ कम होगा
- न्यायिक निष्पक्षता में वृद्धि
- न्याय का लोकतंत्रीकरण

इसलिए इस सेवा का गठन करना चाहिए परंतु इसके चयन की प्रक्रिया, अर्हताओं, प्रशिक्षण आदि को लेकर जो बाधाएं उत्पन्न हैं पहले उनका समाधान किया जाना चाहिए।

इस सेवा के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख भी कीजिए।

इसके गठन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख भी कीजिए।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

निष्कर्ष 2
आगे की राह
(way forward)

(b) क्या आप सोचते हैं कि प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में अंधाधुंध बढ़ोतरी न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही है? चर्चा करें। 6.5

Do you think mushrooming of administrative tribunals is creating a hurdle in judicial processes? Discuss. 6.5

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अर्द्ध-न्यायिक संस्थाएं होती हैं जिनका गठन किसी विशेष प्रयोजन से किया जाता है उदाहरण के लिए पर्यावरणीय समस्याओं एवं मुकदमों के समाधान हेतु राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण।

परंतु अब ऐसा देखा जा रहा है प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों

संवैधानिक प्रावधानों के आगे लिखिए

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

देवनागरी लिपि में लिखिए

भी जटता हो रही है तथा गठन भी हो रहा है जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं—

- न्याय में Overlap की समस्या
- विशेषज्ञों के चयन तथा उनके कार्य प्रणाली से मुकदमों का त्वरित निपटान नहीं
- इन न्यायाधिकरणों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जाने का प्रावधान

चुनौतियों के साथ-साथ लाभों को भी उल्लेख कीजिए

इन सभी को देखते हुए न्याय में बाधा उत्पन्न हो रही है अतः प्रयास यह होना चाहिए कि नये न्यायाधिकरणों का गठन सोच समझकर किया जाना चाहिए साथ ही हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट में लंबित न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वर्ष संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिए निर्णय, सरकार द्वारा 32 ट्रिब्यूनलों को 8 में करने को भी उल्लेख कीजिए।

1/2

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.25	✓
Grade	B	C	D	C	B	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

7. चुनावों के वित्त पोषण से संबंधित पारदर्शिता में सुधार के संदर्भ में किये गए हालिया उपायों पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये तथा राजनीतिक दलों की बेहतर जवाबदेही के लिये कौन-से कदम उठाए जाने चाहिये? (250 शब्द) 12.5

Critically comment on the recent measures taken to improve transparency in electoral funding and what steps should be taken for better accountability of political parties. (250 words) 12.5

चुनाव भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं तथा इनसे ही लोकतंत्र जीवित है परंतु वर्तमान में चुनावों में वित्त का अंधाधुंध उपयोग होने से धनबल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए चुनावों के वित्त पोषण से संबंधित निम्नलिखित हालिया उपाय किये गये है –

— सांसदों / विधायकों के खर्च की सीमा को निर्धारित किया गया (क्रमशः 70 एवं 20 लाख)

— 2000 रुपये से ऊपर के चंदे पर नियंत्रण

— डिजिटल भुगतान

कथन में स्पष्टता का अभाव रहा है

परंतु इन उपायों के बावजूद चुनावों में वित्त का काफी प्रयोग हो रहा है इस संदर्भ में राजनीतिक दलों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं –

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

- दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशों को लागू करना (प्रत्याशियों का व्यय राज्य द्वारा)
- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना।
- सूचना के अधिकार के अंतर्गत दलों को लाना
- दलों के कोष की निगरानी एवं मिले चंदे के स्रोतों का पता लगाना
- प्रणाली एवं दलों के गठबंधन पर नजर
- दलों द्वारा वित्तीय दुरुपयोग एवं अनावश्यक चंदे के संदर्भ में जनजागरूकता बढ़ाना

यदि उपर्युक्त कदम उठाये जाते हैं तो काफी हद तक इन वित्तीय दुरुपयोगों पर अंकुश लगेगा तथा चुनावों में धनबल को रोकने में मदद मिलेगी।

पारदर्शिता के लिए किए गए उपायों के साथ-साथ उनसे जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख कीजिए

3

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

8. यह देखा गया है कि काला धन खपाने के लिये अचल संपत्ति मुख्य क्षेत्रों में से एक है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि कैसे हाल ही में लागू किये गए अचल संपत्ति विनियमन विकास अधिनियम (RERA) से भ्रष्टाचार को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा में मदद मिलेगी? (250 शब्द) 12.5

It is observed that real estate is one of the main domains of placing black money. Critically analyze that how recently adopted RERA (Real Estate Regulation and Development Act) will help in curbing corruption and protecting consumer rights. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

देश में कालाधान ने एक समानान्तर अर्थव्यवस्था का निर्माण कर लिया है तथा इस कालेधन को सफेद करने या छुपाने के लिए अनेक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। इन तरीको में एक उपाय इस कालेधन का निवेश अचल सम्पत्तियों में करना है। क्योंकि यह पर ~~सामान्य~~ दो कारणो से धन लगाया जाता है—

- सुरक्षित रहता है
- पकड़ में जल्दी नहीं आता है।

इसलिए रियल एस्टेट में तेजी से कीमते उछाल खाती है इससे उपभोक्ताओ को काफी नुकसान होता है तथा उन्हें भारी कीमत चुकानी होती है। इन्ही समस्याओं को देखते हुए अचल सम्पत्ति विनियमन विकास

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

अधिनियम लाया गया ताकि इन पर अंकुश लग सके।

इस अधिनियम में रियल एस्टेट में लगे फ्रॉड पन को पकड़ना आसान होगा तथा फ्रॉड पन को चिन्हित किया जायेगा जिससे एक तरफ फ्रॉड पन पर अंकुश लगेगा तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा और वह उचित दामों पर प्रापर्टी खरीद सकेंगे।

परंतु रेरा के क्रियान्वयन को उचित तरीके से करना होगा क्योंकि रियल एस्टेट में काफी प्रभावशाली व्यक्ति सम्मिलित रहते हैं इसलिए इसके उचित क्रियान्वयन से करप्शन की समस्या का समाधान होगा।

अधिनियम के विश्लेषण प्रश्न प्रावधानों के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त लाभों एवं चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।

उचित निष्कर्ष
way forward

1

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

10. एक ऐसा देश जहाँ के अधिकांश नागरिक सरकार की नीतियों तथा सरकार के कामकाज को लेकर अनभिज्ञ हैं, वहीं विभिन्न सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर देना मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

A country in which most of its citizens are unaware of functioning of government and government policies; mandatory Aadhar card link to various services will create a trauma of confusion, analyze. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

आज भी हमारे देश के दूर दराज इलाकों तक न तो शिक्षा का प्रसार हो सका है और न ही वहां जागरूकता में वृद्धि। जिसका परिणाम यह होता है कि नागरिकों को सरकार की नीतियों एवं कामकाज का पता ही नहीं चल पाता है तथा वह विभिन्न योजनाओं को लेकर अनभिज्ञ बने रहते हैं।

तब प्रश्न उठता है कि सरकार के द्वारा विभिन्न सेवाओं आधार कार्ड से जोड़ना दिग्भ्रमित करने वाला फैसला प्रतीत होता है—

— जब विभिन्न सेवाओं की ही जानकारी नहीं है तो जुड़ाव किससे?

— निजता के अधिकार का मुद्दा

— आधार कार्ड भी उपलब्ध नहीं

— गोपनीयता का मुद्दा

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

इन सभी समस्याओं को देखते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच निजता के अधिकार विशेषकर आधार कार्ड के उपयोग को लेकर विचार विमर्श कर रही है।

इन सभी के अलावा सरकार को पहले देश में संचार साधनो, इंटरनेट, मोबाइल, शिक्षा, जागरूकता मंच आदि के माध्यम से लोगो को जागरूक करना चाहिए ~~उसके बाद~~ इस कार्य में डिजिटल इंडिया, ब्राडबैंड मिशन आदि मदद कर सकते हैं। इसके बाद ही सेवाओं को आधार कार्ड से लिंक किया जाना चाहिए तभी अपेक्षित परिणाम मिलेंगे।

आधार कार्ड से जुड़ने पर चुनौतियों के उल्लेख के साथ-साथ इससे प्राप्त लाभों का भी उल्लेख कीजिए

3

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

11. हाल ही में महिला श्रम बल भागीदारी को लेकर एनएसएस के आँकड़ों में प्रदर्शित किया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल की भागीदारी स्थिर हो रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें गिरावट आ रही है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Recent NSS data on women labour force participation has shown that women labour participation is stagnated in urban areas and sharply declining in the rural areas. Critically examine. (250 words) 12.5

देवनागरी लिपि

NSS के आंकड़ो के अनुसार देश के नगरीय क्षेत्रों में महिला श्रम बल में बढ़ोत्तरी नहीं हो रही है बल्कि इसकी भागीदारी स्थिर है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट की स्थिति है।

इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं

- महिलाओं को उचित अवसर का अभाव
- कुशलता की कमी
- कम अवसर
- शिक्षा की कमी - ग्रामीण क्षेत्रो में
- जागरूकता नहीं
- समान वेतन नहीं - नगरो में
- कृषि - ग्रामीण क्षेत्र में मशीनीकरण
- प्रवास
- कार्यस्थल पर शोषण

इन सभी कारकों से महिला श्रम बल

भूमिका में प्रश्न की बात दोहराने की बजाय अपने उत्तर के संदर्भ में उचित रूप से सामग्री का उल्लेख कीजिए

एन.एस.एस. के संदर्भ में एन एस एस के महत्वपूर्ण आँकड़ों का उल्लेख भी कीजिए

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation
कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)
कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

A3

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

भागीदारी में गिरावट आ रही है जिससे निम्नलिखित नुकसान हो सकते है -

- लैंगिक असमानता में वृद्धि
- महिलाओं के शोषण में वृद्धि
- जनांकिकीय लाभांश का उचित लाभ नही
- समावेशी विकास में बाधा

इसलिए सरकार को प्रयास करना चाहिए कि महिलाओं को उचित मौके दिये जाये तथा वह श्रम बल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर राष्ट्र निर्माण में भूमिका अदा कर सकें।

निष्कर्ष के साथ आगे की राह (way forward) का पर्याप्त उल्लेख कीजिए

(4)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

12. प्राचीन काल में धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज का महत्त्वपूर्ण विशेषता थी। हाल ही में धर्मनिरपेक्षता शब्द को समाचार माध्यमों में लगातार उछाला जाता रहा है। इस संदर्भ में वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण कीजिये, क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता खतरे में है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

From ancient times secularism was essential feature of Indian society. Recently the term secularism was flaunted continuously in media news. Analyze the current scenario in this regard; is secularism in India at risk? Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं इसलिए प्राचीन भारतीय समाज की एकता का आधार धर्मनिरपेक्षता रहा है।

धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को भारतीय संविधान द्वारा भी स्थापित किया गया। जिसका अर्थ है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा तथा सभी व्यक्ति अपने-अपने धर्म को मानने एवं आचरण करने के लिए स्वतंत्र होगें।

परंतु इसके साथ ही धर्म के नाम पर झगड़े, दंगे एवं संघर्ष विभिन्न समयों पर होते रहे हैं वर्तमान में भी सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में धर्मसापेक्षता एवं धर्मनिरपेक्षता का द्वंद्व लगातार दिखायी पड़ता है। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में है —

धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में प्राचीन से वर्तमान के मध्य की पृष्ठभूमि का संक्षिप्त लेकिन उचित उल्लेख करते हुए उत्तर लिखिए

वर्तमान संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लेख कीजिए

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

- धर्म का राजनीतिकरण के कारण
- विभिन्न धर्मों में वैमनस्य के कारण
- अफवाहों के कारण
- धर्म का राजनीतिकरण
- धर्म को वोट बैंक से जोड़ना

इसी परिप्रेक्ष्य में चाहें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के दंगे हो या बरेली, मऊरानीपुर के दंगे। इसी के साथ गौ रक्षकों द्वारा उत्तेजक भाषण, मुहर्रम के दौरान भड़कीले जुलूस, कांवड़ियों द्वारा चक्का जाम आदि को लेकर भय का वातावरण बना रहता है।

परंतु इसके बावजूद धर्म निरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र व समाज की आत्मा है इसलिए इस पर खतरा नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकार, जनता, नागरिक समाज, प्रशासन और द्वारा इन तुच्छ घटनाओं को रोकने की त्वरित कार्यवाही होती है।

आपने अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास किया है

4

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

13. भारत सरकार अपने नागरिकों की खाद्य-सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित कर रही है लेकिन किसानों की सुरक्षा दिन-प्रतिदिन बिगडती जा रही है। खाद्य-सुरक्षा की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय भी सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Indian government is focusing on food security of its citizen but farmer's security deteriorating day by day. Critically examine challenges for food security and also mention suggestion for improvement of conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

खाद्य-सुरक्षा का अर्थ है सभी व्यक्तियों को प्रत्येक समय पर उचित मूल्य से गुणवत्तापूर्ण खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करना। भारत में कुपोषण, बीमारी, भुखमरी आदि की समस्या को देखते हुए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैसे खाद्य सुरक्षा मिशन, अन्नपूर्णा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय योजना आदि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराती है तथा दूसरी तरफ कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु कृषि एवं किसान विकास पर भी बल देती है।

इन सबके बावजूद किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है —

— किसानों की आत्महत्या में वृद्धि
— किसानों के ऋणों में वृद्धि
— किसानों में बढ़ता कुपोषण, निराशा

किसानों की बिगड़ती सुरक्षा के पीछे के कारणों का भी उल्लेख कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न सख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

- कृषक अशांति — मंदसौर की घटना
- कृषकों का बढ़ता शोषण

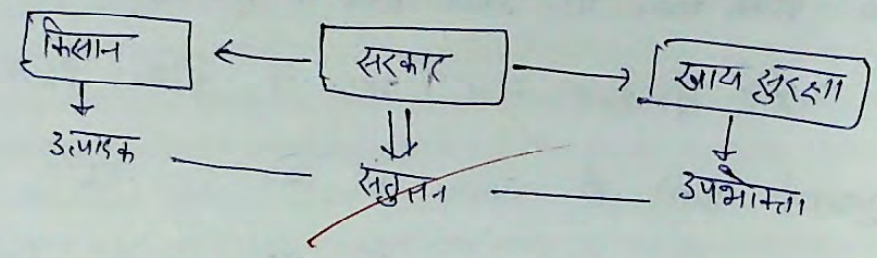

इसलिए सरकार को निम्नलिखित रणनीति पर विचार करना चाहिए—

अर्थात सरकार को उपभोक्ता एवं कृषक दोनों में सामंजस्य बनाने का प्रयास कर निम्न लिखित कृषक सुधार हेतु करने चाहिए—

- कृषि में संरचनात्मक सुधार - बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि।
- संस्थागत सुधार
- किसानों की कर्ज माफी - कृषक जनसंख्या में सुधार

किसान कल्याण जैसी योजनाएँ

उपर्युक्त उपायों को अपनाकर कृषक सुधार को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

प्रमुख उपायों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कीजिए

(2)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

14. भारत में एकल परिवार का प्रचलन संयुक्त परिवार से अधिक होता जा रहा है क्योंकि भारतीय समाज समूह की अपेक्षा व्यक्तिवाद की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Trends of nuclear family in India are more common than joint family as Indian society is heading towards more individualism than community. Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

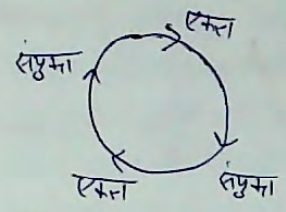

भारत में परिवार चक्र के माध्यम से संयुक्त एवं एकल परिवार के संबंध को समझा जा सकता है –

अर्थात संयुक्त परिवार एकल परिवार में एवं एकल परिवार संयुक्त परिवार में बदलते रहते हैं।

वर्तमान में संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं जिसके कारण निम्नलिखित हैं –

- आधुनिक मूल्यों का प्रभाव
- औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण
- आधुनिक शिक्षा का प्रभाव
- प्रवजन
- अत्यधिक जनसंख्या दबाव
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं स्वच्छन्दता की चाह

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

- सामूहिकता की भावना में कमी।

इस प्रकार एकल परिवार के कई कारण हैं यद्यपि व्यक्तिवाद की ओर आकर्षण अन्य कारणों में प्रमुख कारण है क्योंकि आधुनिक शिक्षा एवं मूल्यों के कारण व्यक्ति स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है दूसरा अब व्यक्ति को रोजगार के लिए दूर देशों तक प्रवास करना होता है जिसके कारण समूह में रह पाना संभव नहीं हो पाता और व्यक्तिवादिता के कारण एकल परिवार को बढ़ावा मिलता है।

परंतु इसके साथ ही एकल परिवार रहने के स्तर पर एकल हो परंतु त्यौहारों, शादी-समारोह आदि के अवसर पर सामाजिकता एवं सामूहिकता का परिचय देता है जो भारतीय समाज की अनूठी विशेषता है।

व्यक्तिवाद एवं एकल संयुक्त परिवार की वास्तविकता के आधार पर आगे आयामों पर उचित ध्यान दीजिए

निष्कर्ष को आगे की राह (Way forward) के रूप में प्रस्तुत कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

15. हमारी शिक्षा प्रणाली बड़े राजनीतिक समुदाय के रूप में ग्रामीणों को एकीकृत करने में असफल रही है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 12.5

Our education system has failed to integrate the rural into the larger political community. Comment. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

हमारी शिक्षा प्रणाली परम्परागत एवं आधुनिक मूल्यों के संयोजन से निर्मित हुई है जिसमें आधुनिकता के तत्व ज्यादा हैं।

हमारी शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता है कि यह रोजगार उन्मुख ज्यादा है ~~जिसका प्रभाव हुआ~~ कि साथ ही शिक्षा का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम हो पाया। जिसका प्रभाव यह हुआ कि ग्रामीणों मे राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो पाया - जिसे हम निम्न बिन्दुओं से समझ सकते हैं—

— आज भी ग्रामीण भारत राजनीतिक जनजागरूकता में अपरिपक्व
— मतदान व्यवहार - धर्म, जाति के आधार पर
— अपने हितो को लेकर जागरूक नहीं
— राष्ट्रीय भावना की कमी

इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक

दर्ज की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से परिवर्तनों और सकारात्मक नजरिए से उल्लेख कीजिए

2
1

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

चेतना का विकास किया जाना चाहिए—

- संवैधानिक संस्थाओं के प्रसार द्वारा
- शिक्षा संस्थाओं एवं पंचायती राज के संयोजन द्वारा
- चुनाव के माध्यम से
- मीडिया द्वारा

इन उपायों को अपनाकर देश में ग्रामीण क्षेत्रों को राजनीतिक समुदाय के रूप में समेकित किया जा सकता है जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।

उत्तर में तथ्यों, उदाहरणों एवं आंकड़ों का और अधिक समावेश कीजिए।

शब्द-सीमा का ध्यान रखिए।

3

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

16. यह माना जाता है कि विमुद्रीकरण नकदी-विहीन समाज को प्रेरणा देकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों की विफलताओं की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 12.5

It is believed that the demonetization will provide thrust to the welfare programmes by providing stimulus to cashless society. Discuss this statement in the backdrop of failures of various welfare programmes. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

विमुद्रीकरण का तात्पर्य है कि प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करना या उस पर रोक लगाना जैसे हाल ही में 500 एवं 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया।

विमुद्रीकरण के पीछे जो उद्देश्य था वह था - जाली नोटों को बाहर करना, कैशलेस समाज का निर्माण, आतंकियों के वित्तपोषण को समाप्त करना आदि। इसके साथ ही विमुद्रीकरण नकदी-विहीन समाज को प्रेरणा देता है जिसके कारण कल्याणकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलता है जैसे -

- DBT - द्वारा सीधे खातों में पैसा भेजना
- काले धन पर अंकुश - योजनाओं का उचित क्रियान्वयन
- भ्रष्टाचार पर अंकुश -
- योजनाओं के लीकेज में कमी

विमुद्रीकरण के उद्देश्यों को साथ-साथ लिखें

देवनागरी लिपि

प्रोटीन, परन्तु संस्थित रूप और शीर्षक

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
Please don't write anything in this space)

इस संदर्भ में हम देखे तो पाते हैं पहले की कई योजनाएं जैसे- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सब्सिडी का ट्रांसफर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ - ये कहीं-न कहीं उचित क्रियान्वयन न होने की वजह से असफल हो गई।

इसलिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देकर निश्चित रूप से सरकारी योजनाओं का ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकता है जिसका वास्तविक लाभ जनता को ही मिलेगा।

सुधार की आवश्यकता ... व्यवहारिक स्तर पर ... ध्यान रखिए।

निष्कर्ष में आगे की राह (Way forward) के रूप प्रस्तुत कीजिए

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

18. किसानों की कृषि ऋण माफी केवल अस्थायी राहत है। उक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा किसानों की स्थिति को सुधारने हेतु उपाय सुझाइये। (250 शब्द) 12.5

Waiving off farm loans is only temporary relief to the farmers. Critically examine above statement and give your suggestions for improving conditions of farmers. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

किसानों पर बढ़ते कर्ज को देखते हुए सरकारों द्वारा उनके कर्ज को माफ किया जा रहा है जैसे- पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि में।

परंतु यदि हम पुराने अनुभवों से सीखें तो 2007-2008 में केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर कृषकों के ऋण माफ किये गये थे परन्तु उसका लाभ स्थायी रूप से नहीं मिला क्योंकि वही किसान दोबारा ऋण जाल में फंस गये। इस ऋण माफी के निम्न नुकसान भी है —

- अकर्मण्यता को बढ़ाता है
- राजकोषीय व्यय बढ़ता है
- सरकार की क्षमता कमजोर होती है
- जो किसान ऋण दे चुके थे वे बंद आवश्यक नच जाते हैं।

अतः प्रश्न उठता है कि कर्जमाफी एक

कृषि ऋण माफी के आलोचनात्मक परीक्षण के अंतर्गत सकारात्मक पक्ष का भी नकारात्मक पक्ष के उचित उल्लेख ... लिखें

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

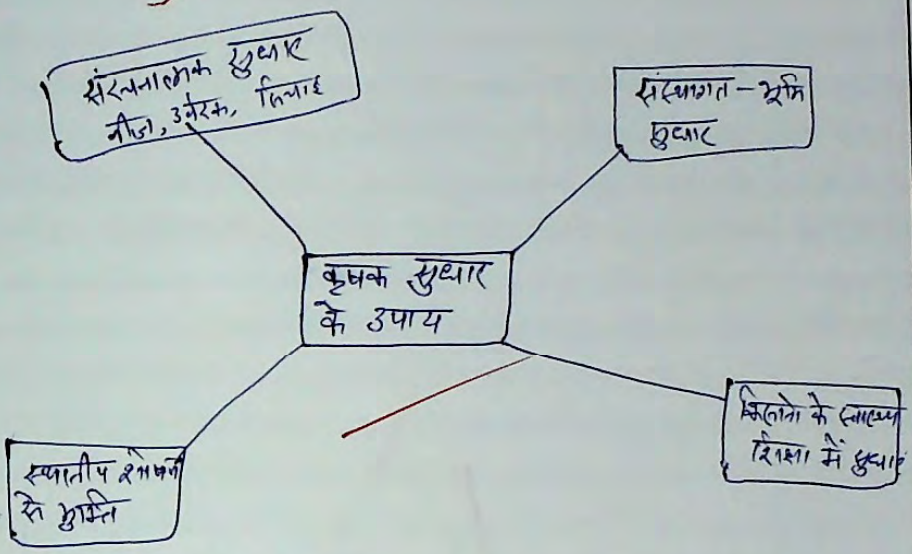

चुनावी स्टंट नहीं होना चाहिए बल्कि किसानों की दशा को सुधार के निम्न उपाय होने चाहिए –

इसके अतिरिक्त जो योजनाएं चल रही हैं जैसे - कृषक बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान चैनल, सिंचाई योजनाएं उनका बेहतर क्रियान्वयन हो और खेत आधारित रणनीति को अपनाया जाना चाहिए जैसे - रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड मैनेजमेंट, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि।

निष्कर्ष भी लिखिए

3

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

A3

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

Copyright – Drishti The Vision Foundation